कानपुर, गुरुवार, 12 मार्च, 2026 वर्षः 03, अंकः 65, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड छुट्टी से निवेश तक सब दर्ज करना होगा पोर्टल पर...>Pg12

जंग की तपिश से घिरा कानपुर ...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

कानपुर के कई नाले बिना पूरी सफाई के सीधे गिर रहे गंगा में

गंगा में घुल रहा शहर का गंदा सच

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कानपुर में हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहर के कई बड़े और छोटे नाले अब भी बिना पूरी सफाई के सीधे गंगा में गिर रहे हैं। नालों से बहकर आने वाला काला और बदबूदार पानी न सिर्फ नदी की सेहत बिगाड़ रहा है, बल्कि गंगा किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं के लिए भी चिंता का कारण बन गया है। कई घाटों के पास यह गंदा पानी साफ दिखाई देता है, जिससे स्वच्छता के दावों पर सवाल उठ रहे हैं।

कानपुर में सीसामऊ, परेड, परमट, नवाबगंज, जाजमऊ और अन्य क्षेत्रों से निकलने वाले कई नाले गंगा में गिरते हैं। इनमें से कुछ नालों को इंटरसेप्टर के जरिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई स्थानों पर यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं है। परिणामस्वरूप घरेलू सीवेज, प्लास्टिक कचरा और अन्य अपशिष्ट सीधे गंगा में मिल रहे हैं। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के तहत कानपुर में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। शहर में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी बनाए गए हैं, ताकि नालों के पानी को शुद्ध कर गंगा में छोड़ा जा सके। इसके बावजूद कई नालों का पानी बिना उपचार के नदी में जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि शहर की आबादी बढ़ने के साथ सीवेज का दबाव भी बढ़ा है। मौजूदा सीवेज सिस्टम कई जगहों पर क्षमता से अधिक लोड झेल रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जब नालों का पानी सीधे गंगा में पहुंचने लगता है। पर्यावरण से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि नालों के पानी को पूरी तरह ट्रीट कर गंगा में छोड़ा जाए तो नदी की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है। इसके लिए सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करना और सभी नालों को इंटरसेप्टर सिस्टम से जोड़ना जरूरी है। वही स्थानीय व घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार गंगा के किनारे नालों से आने वाला गंदा पानी साफ दिखाई देता है, जिससे स्नान और पूजा-पाठ के दौरान असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहती है।

ठोस कदम नहीं उठाए गए तो...

गंगा भारत की आस्था और जीवनरेखा मानी जाती है, लेकिन कानपुर जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गंगा की स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों की राय है कि सभी बड़े नालों को एसटीपी से जोड़ना जरूरी है। साथ ही पुराने सीवरेज नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाए। औद्योगिक अपशिष्ट की सख्त निगरानी हो व गंगा किनारे ठोस कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए।

सीवेज ट्रीटमेंट के दावों के बीच कई जगहों से गंदा पानी सीधे नदी में, पर्यावरण और आस्था दोनों पर संकट

मुख्य कारण

- बढ़ती आबादी और सीवेज का दबाव
- कई इलाकों में अधूरा सीवर नेटवर्क
- बरसात में ओवरफ्लो होकर नालों का पानी सीधे गंगा में पहुंचना

गंगा प्रदूषण का असर

- नदी के पानी की गुणवत्ता में गिरावट
- जलीय जीवों और मछलियों पर खतरा
- स्नान व धार्मिक गतिविधियों के दौरान स्वास्थ्य जोखिम
- गंगा किनारे रहने वाले लोगों पर दुर्गंध और संक्रमण का खतरा

कानपुर में गंगा और नालों की स्थिति

- करीब 30-35 छोटे-बड़े नाले कानपुर शहर से निकलकर गंगा में गिरते हैं
- सीसामऊ सहित कई बड़े नालों को इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया है
- लगभग 15-20 नालों के पानी को शोधन के लिए ट्रीटमेंट प्लांट तक मोड़ने की व्यवस्था की गई है
- 10 से अधिक छोटे नाले अभी भी आंशिक रूप से या सीधे गंगा में गिरने की शिकायतों में शामिल रहते हैं
- शहर में करीब 450-500 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, लेकिन सीवेज की मात्रा कई बार इससे अधिक हो जाती है।

गंगा में गिरने वाले प्रमुख नाले

- सीसामऊ नाला - शहर का सबसे बड़ा नाला, लंबे समय तक सीधे गंगा में गिरता रहा, बाद में इंटरसेप्टर से जोड़ा गया।
- परेड नाला - शहर के घनी आबादी वाले इलाके का सीवेज लेकर गंगा में पहुंचता है।
- परमट नाला - घरेलू गंदे पानी और कचरे का बड़ा स्रोत, सीधे गंगा में प्रवाह।
- नवाबगंज नाला - कई मोहल्लों का सीवेज लेकर गंगा तट तक पहुंचता है।
- जाजमऊ क्षेत्र के नाले - टेनरी और अन्य औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट का दबाव भी रहता है।

इन घाटों के पास ज्यादा दिखता है नालों का गंदा पानी

- **परमट घाट क्षेत्र** - आसपास के नालों का पानी गंगा में मिलने से कई बार पानी का रंग बदलता दिखाई देता है और दुर्गंध की शिकायत रहती है।
- **नवाबगंज घाट** - स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पास के नालों से आने वाला गंदा पानी अक्सर सीधे गंगा में मिलता दिखाई देता है।
- **सिद्धनाथ घाट (जाजमऊ क्षेत्र)** - शहर के सीवेज और औद्योगिक क्षेत्र के प्रभाव के कारण इस इलाके में प्रदूषण की समस्या लंबे समय से चर्चा में रही है।
- **मैस्कर घाट** - आसपास के ड्रेनेज का पानी नदी में मिलने से यहां भी पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात सामने आती रहती है।

शहर में बढ़ रहा अतिक्रमण और पेयजल का मुद्दा

निरीक्षण पर निकले नगर आयुक्त को कई जगह दिखा अतिक्रमण

फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने, सी.एण्ड.डी. वेस्ट साफ कराने और क्षतिग्रस्त पाइप लाइन दुरुस्त करने के दिए आदेश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।नगर निगम के नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर सफाई, अतिक्रमण और पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मोतीझील, अमर जवान चौराहा, अशोक नगर, 80 फिट रोड, भदौरिया चौराहा, लेनिन पार्क चौराहा, पी रोड और गांधी नगर सहित कई स्थानों का भ्रमण किया गया। इस दौरान जलकल विभाग के महाप्रबंधक, अधिशासी अभियंता जलकल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान 80 फिट रोड से भदौरिया चौराहा होते हुए लेनिन पार्क तक सड़क किनारे फुटपाथ पर बड़ी संख्या में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण पाए गए। कई स्थानों पर भवन स्वामियों द्वारा फुटपाथ पर दीवारें बना लेने से राहगीरों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा था। इस पर नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी और जोनल अभियंता-4 को संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने और यूजर चार्ज की वसूली करने के निर्देश दिए। साथ ही सप्ताह में दो दिन नियमित निरीक्षण कर दोबारा अतिक्रमण न होने देने के आदेश दिए।

इसी तरह जरीब चौकी से पी रोड होते हुए गोपाल सिनेमा और सीसामऊ बाजार के अंदर वनखंडेश्वर मंदिर चौराहे तक सड़क व फुटपाथ पर भी भारी अतिक्रमण पाया गया, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। नगर आयुक्त ने इस मुख्य मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए निरंतर अभियान चलाने तथा राजस्व निरीक्षक की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण करने वालों से प्रतिदिन यूजर चार्ज वसूलने और सामान जब्त करने के भी निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान लेनिन पार्क ढाल पर जलकल पंप के बाहर काफी मात्रा में सीएण्डडी वेस्ट पड़ा मिला। इस पर जोनल अभियंता-4 को तत्काल कचरा उठाने और संबंधित से यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए गए।गांधी नगर और लेनिन पार्क क्षेत्र में पेयजल समस्या की शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। जलकल विभाग ने बताया कि पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ स्थानों पर दूषित जलापूर्ति हो रही थी। क्षतिग्रस्त पाइप लाइन निकालकर नई लाइन डाली जा रही है, जिसके बाद जल्द ही शुद्ध जलापूर्ति सुचारु हो जाएगी। नगर आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि मरम्मत पूरी होने तक क्षेत्र में प्रतिदिन पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो।

गैस संकट पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, खाली सिलेंडर लेकर जताया विरोध

» 14 मार्च को आप करेगी प्रदर्शन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर में गैस किल्लत और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मेस्टन रोड पर खाली सिलिंडर लेकर प्रदर्शन किया। वहीं, आम आदमी पार्टी ने 14 मार्च को आंदोलन का बिगुल फूंका है।एलपीजी के दाम बढ़ने और शहर में गैस सिलिंडरों की किल्लत के विरोध में महानगर कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन किया। पार्टी महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मेस्टन रोड पर दुकानदारों के बीच खाली सिलिंडर लेकर नारेबाजी की। पवन गुप्ता ने कहा कि गैस सिलिंडर की कीमतें बढ़ने और त्योहार के समय आपूर्ति में कमी के कारण आम जनता और कारोबारी दोनों को परेशानी हो रही है, जिससे कालाबाजारी भी बढ़ गई है। प्रदर्शन के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि जल्द ही एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति सामान्य नहीं की गई, तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तेज करेगी। इस मौके पर इकबाल अहमद, शंकर दत्त मिश्रा, विनोद अवस्थी, राम शंकर राय, राकेश साहू, चंद्र मनी मिश्रा, पदम मोहन मिश्रा, रितेश यादव, जावेद उस्मानी, राज किशोर वर्मा, मुकेश कन्नौजिया सहित कई लोग मौजूद रहे।आम आदमी पार्टी की ओर से बुधवार को महिला कार्यकर्ता संवाद का आयोजन काकादेव स्थित गेस्ट हाउस में किया गया। पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दामों में वृद्धि होने से आम आदमी की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम भी फिर से न बढ़ा दिए जाएं। जिलाध्यक्ष अनुज शुक्ला ने बताया कि 14 मार्च को जिला मुख्यालय में पार्टी प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर महासचिव रेखा जायसवाल, महानगर महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रमा अवस्थी, निशा निगम, पुष्पा सिंह, सरिता, सिमरन जीत कौर आदि मौजूद रहीं।

चोरियां खोलो या थानेदारी छोड़ो पुलिस आयुक्त ने दी सख्त चेतावनी

मासिक अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने दिए कड़े निर्देश लंबित मामलों के जल्द खुलासे और त्योहारों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के आदेश

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। पुलिस कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त ने कलक्टरगंज थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए थानाध्यक्ष को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि या तो चोरियों का जल्द खुलासा करें या फिर थानेदारी छोड़ने के लिए तैयार रहें।

बैठक में अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) डॉ. विपिन ताडा, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध संकल्प शर्मा सहित शहर के सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी तथा थाना और शाखा प्रभारियों ने भाग लिया।

अपराध समीक्षा के दौरान पुलिस आयुक्त ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और प्रभावी पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए भी विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सूखे नशे के खिलाफ अभियान तेज करने, पेट्रोल व एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने तथा साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए।पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जनशिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा पुलिस की मौजूदगी हर क्षेत्र में दिखाई दे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार भी पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

कामर्शियल के साथ घरेलू गैस की किल्लत, कारोबार और रसोई दोनों पर संकट

जंग की तपिश से घिरा कानपुर

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा दबाव अब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में भी साफ दिखाई देने लगा है। शहर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के साथ-साथ घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता भी प्रभावित होने लगी है। इससे एक ओर होटल-रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबारियों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों की रसोई भी संकट में आ गई है।

शहर में गैस एजेंसियों और गोदामों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को जहां कमर्शियल सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। कई एजेंसियों पर उपभोक्ताओं को अगले दो-तीन दिन बाद डिलीवरी का समय दिया जा रहा है।

शहर में करीब 200 बड़े होटल, 3500 से अधिक रेस्टोरेंट और ढाबे तथा लगभग 1500 गेस्ट हाउस संचालित हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों में रोजाना हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और इसके लिए प्रतिदिन करीब 3000 कमर्शियल गैस सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपूर्ति में आई रुकावट के कारण कई प्रतिष्ठानों के सामने रसोई बंद करने की नौबत आ रही है। होटल संचालकों का कहना है कि सामान्य दिनों में एक मध्यम आकार के रेस्टोरेंट को रोजाना दो से तीन सिलेंडरों की आवश्यकता होती है, जबकि मौजूदा हालात में एक सिलेंडर भी समय पर मिलना मुश्किल हो गया है।

वहीं घरेलू उपभोक्ताओं की परेशानी भी बढ़ गई है। कई इलाकों में गैस डिलीवरी में देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। गृहिणियों का कहना है कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर आने में तीन से चार दिन लग रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग गैस खत्म होने पर पड़ोसियों से अस्थायी सिलेंडर लेकर काम चला रहे हैं।

- पश्चिम एशिया तनाव का असर स्थानीय बाजार तक
- होटल-रेस्टोरेंट के साथ घरों में भी सिलेंडर के लिए इंतजार
- गोदामों पर कतार और कालाबाजारी की शिकायतें

सहालग में गेस्ट हाउस और कैटरिंग कारोबारियों पर दबाव

इन दिनों शहर में विवाह समारोहों का सीजन चल रहा है। ऐसे में गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन और कैटरिंग कारोबारियों के सामने गैस की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बड़े कार्यक्रमों के लिए बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों की जरूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालात में सिलेंडर मिलना कठिन हो गया है। कई व्यापारियों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर गैस सिलेंडर ब्लैक में ऊंची कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। इससे छोटे कारोबारियों और ढाबा संचालकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

रसोई चलाने के लिए अपनाने पड़ रहे विकल्प

कमर्शियल गैस की कमी के कारण कई होटल और रेस्टोरेंट संचालक अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं का सहारा लेने लगे हैं। कुछ जगहों पर लकड़ी और कोयले से खाना बनाया जा रहा है, जबकि छोटे प्रतिष्ठान इंडक्शन चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इससे लागत बढ़ रही है और काम की गति भी धीमी पड़ रही है। मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य उत्पादों से जुड़े व्यापारियों पर भी इस संकट का असर दिखाई देने लगा है। उत्पादन में कमी आने लगी है। दूसरी ओर कोयले की मांग अचानक बढ़ने से उसके दाम भी बढ़ गए हैं। पहले 1750 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला कोयला अब करीब 1900 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है।

गोदामों पर सुबह से कतार, खाली हाथ लौट रहे लोग

कानपुर में गैस की किल्लत का सबसे स्पष्ट नजारा गैस एजेंसियों और गोदामों पर दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर होटल और रेस्टोरेंट संचालक सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। घरेलू उपभोक्ताओं की स्थिति भी अलग नहीं है। कई एजेंसियों पर सीमित संख्या में ही सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे ही ट्रक पहुंचता है, कुछ ही देर में पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है। छोटे ढाबा और ठेला संचालकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उनके पास अतिरिक्त सिलेंडर रखने की क्षमता नहीं होती, इसलिए एक दिन गैस न मिलने पर उनका पूरा कामकाज ठप हो जाता है।

- कानपुर में रोजाना लगभग 3000 कमर्शियल गैस सिलेंडरों की खपत
- शहर में 3500 से ज्यादा रेस्टोरेंट और ढाबे सक्रिय
- 200 होटल और 1500 गेस्ट हाउस गैस आपूर्ति पर निर्भर
- कोयले की कीमत 1750 से बढ़कर 1900 रुपये प्रति क्विंटल
- सहालग के चलते गैस की मांग सामान्य से कहीं अधिक

प्रशासन की क्या तैयारी

- जिलाधिकारी ने गैस एजेंसियों और आपूर्ति विभाग से रिपोर्ट तलब की
- शहर में कमर्शियल व घरेलू गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
- कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतों पर कड़ी निगरानी
- जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने की योजना
- व्यापार संगठनों के साथ समन्वय बैठकें करने की तैयारी

व्यापारियों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए होटल-रेस्टोरेंट संगठनों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने बुधवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कमर्शियल गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन गैस कंपनियों और आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय कर स्थिति को जल्द सामान्य करने के प्रयास कर रहा है। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्यों पैदा हुआ गैस का संकट?

- पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित
- समुद्री परिवहन और बीमा लागत बढ़ने से एलपीजी आयात महंगा
- देश के कई हिस्सों में मांग अचानक बढ़ी
- सहालग और पर्यटन सीजन से कमर्शियल गैस की खपत बढ़ी
- स्थानीय स्तर पर वितरण में अव्यवस्था और संभावित जमाखोरी

अगर संकट लंबा चला तो क्या होगा असर?

- होटल-रेस्टोरेंट उद्योग में अस्थायी बंदी की नौबत
- मिठाई, नमकीन और फूड इंडस्ट्री का उत्पादन घटेगा
- शादी-समारोह और कैटरिंग सेवाएं प्रभावित होंगी
- कोयला, लकड़ी जैसे विकल्पों की कीमतों में तेजी
- हजारों कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा पर खतरा

क्या आम लोगों की थाली महंगी होगी?

- गैस की किल्लत से होटल और ढाबों की लागत बढ़ रही
- कोयला और वैकल्पिक ईंधन के दाम बढ़ने लगे हैं
- मिठाई, नमकीन और फास्ट फूड के दाम बढ़ने की आशंका
- शादी और कैटरिंग सेवाओं का खर्च बढ़ सकता है
- बाहर खाने-पीने की कीमतों में बढ़ोतरी संभव

नशे के खिलाफ कानपुर के 52 थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया। इस विशेष ड्रिल के तहत बुधवार को शहर के सभी 52 थाना क्षेत्रों में एक साथ हजारों पुलिसकर्मियों ने व्यापक स्तर पर छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाया।

युवाओं में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए हजारों पुलिसकर्मी उतरे मैदान में

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में बाहर से आ रहे मादक पदार्थों की सप्लाई को रोकना और स्थानीय स्तर पर इनकी बिक्री करने वाले तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना था। इसके लिए शहर के प्रमुख चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई।अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने पान की दुकानों, संदिग्ध ठिकानों और संभावित तस्करी के अड्डों पर भी छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में गोगो (पेपर रोल) सहित अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने कई स्थानों पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान युवाओं को नशे की लत से बचाने और शहर में मादक पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नशे का अवैध कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अभियान के चलते शहर भर में पान दुकानदारों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति रही। कई स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी के कारण संदिग्ध गतिविधियां भी बंद हो गईं। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। छापेमारी समाप्त होने के बाद बरामदगी और की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

गंगा मेला पर समाजसेवी हिमांशु त्रिवेदी ने कराया होली मिलन समारोह

कौशलपुरी के नागरिकों ने मनाया उत्सव

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला के अवसर पर समाजसेवी हिमांशु त्रिवेदी द्वारा कौशलपुरी क्षेत्र में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।समारोह के दौरान रंगों और उत्साह का माहौल देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे के साथ होली की खुशियां साझा कीं और गंगा मेला के पारंपरिक उत्सव को पूरे उल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या मौजूद रही।

इस अवसर पर हिमांशु त्रिवेदी ने कहा कि होली का पर्व प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज में आपसी मेल-मिलाप और भाईचारे को मजबूत करते हैं। उन्होंने सभी लोगों को गंगा मेला और होली की शुभकामनाएं भी दीं।

कार्यक्रम में शिवांशु त्रिवेदी सहित कौशलपुरी के समस्त नागरिक उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर होली मिलन समारोह को उत्साहपूर्वक संपन्न किया।

मिशन शताब्दी: आरएसएस की संगठनात्मक संरचना में बड़े बदलाव की तैयारी

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संगठनात्मक सरंचना 15 मार्च से बदलने की तैयारी है। यह घोषणा 13 मार्च से हरियाणा में होने वाली संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के तुरंत बाद हो जाएगी। इस बदलाव में प्रांत और क्षेत्र की जगह प्रांत को संभाग और क्षेत्र इकाई को राज्य इकाई में बदलने की तैयारी है। ऐसे में प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक का पद की जगह अब संभाग प्रचारक और राज्य प्रचारक कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर कानपुर प्रांत जिसमें झांसी तक का क्षेत्र आता है।

अब उसे दो भागों में बांटकर कानपुर संभाग और झांसी संभाग कर दिया जाएगा। झांसी संभाग में बुंदेलखंड के जिलों को रखा जाएगा। इसी तरह वर्तमान में क्षेत्र की तीन इकाईयां हैं, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तराखंड क्षेत्र। अब इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। राज्य प्रचारक इन तीनों का प्रमुख होगा। प्रतिनिधि सभा की इस बैठक में शामिल होने के लिए संघ के सभी प्रांत स्तरीय पदाधिकारियों को हरियाणा बुलाया गया है। कानपुर से प्रांत प्रचारक, प्रांत संघ चालक, प्रांच प्रचारक प्रमुख, सह प्रांत प्रचारक सहित ऐसे सभी

पदाधिकारी बुधवार को शहर से सभा में शामिल होने गए हैं।

लंबे समय के बाद किया जा रहा है बदलाव

बताया जा रहा है कि इस सभा में दो दिनों तक कई सत्र होने के बाद 15 मार्च को पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर राष्ट्रीय स्तर पर उनके स्थान और पद परिवर्तन के संबंध में जानकारी दी जाएगी। संघ की संरचना में यह बदलाव लंबे समय के बाद किया जा रहा है। शताब्दी वर्ष में इस बदलाव को संघ से ज्यादा-ज्यादा लोगों को जोड़ने और उनके बीच पकड़ बनाने की दिशा में उचित कहा जा रहा है। करीब पांच महीने पहले कानपुर आए सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संघ पदाधिकारियों से इस तरह के बदलाव के लिए तैयार रहने को कहा था।

भाजपा जिला इकाइयों से पहले संघ में परिवर्तन की तैयारी

भाजपा की क्षेत्रीय इकाई और जिला इकाइयों में बदलाव की प्रक्रिया चल ही रही थी कि संघ की संरचना और पदाधिकारियों के बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि इस पर लंबे समय से काम चल रहा था। भाजपा के जिला इकाइयों की कार्यकारिणी में बदलाव के लिए सभी जिला पर्यवेक्षकों की ओर से कार्यकारिणी में रखे जाने वाले नाम की सूची पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन के पास जमा कर दिया है लेकिन प्रदेश संगठन मंत्री क्योंकि संघ का ही अगं होते हैं, ऐसे में उन्हें भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिलों की कार्यकारिणी की सूची 15 मार्च के बाद जारी हो सकती है।

सम्पादकीय

दूषित पानी शुद्ध करने की संवेदनशील पहल

अक्सर कहा जाता है कि जल ही जीवन है। लेकिन यह जल यदि दूषित हो तो क्या इसे जीवन कहा जा सकता है? यूं तो देश के गांवों में महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन जोर-शोर से चलाया जाता रहा है। लेकिन यह बात परेशान करती है कि पेयजल का बड़ा हिस्सा प्रदूषित पाया गया है। लोग सेहत के लिये हानिकारक जल पीने को मजबूर हैं। फलत- इससे उत्पन्न बीमारियों की चुनौतियों का सामना करने को बाध्य होते हैं। यह हमारे नीति-नियंताओं की विफलता ही कही जाएगी कि देश के करोड़ों लोग आज भी स्वच्छ जल की उपलब्धता से वंचित हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश के तमाम इलाकों में लिए गए दूषित पेयजल नमूनों के करीब दो तिहाई हिस्से को शुद्ध करने के प्रयास नहीं हुए हैं। जो इस बात को दर्शाता है कि आज भी देश के करोड़ों लोग स्वच्छ पेयजल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति हमारे विकास के मॉडल व तरक्की के दावों की तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। यही वजह है कि दूषित जल से होने वाले रोगों का दायरा बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है कि जोर-शोर से घर-घर नल से जल पहुंचाने की सार्थक पहल की गई। निस्संदेह, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे अपने घर में स्वच्छ पेयजल मिले। इसी मकसद से साल 2019 में जल जीवन मिशन को सिरे चढ़ाया गया था। लेकिन इस योजना के सुरक्षित तरीके से संचालन और स्वच्छ जल आपूर्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। यह हकीकत है कि जब लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलता तो कई तरह के रोगों के पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कहा भी जाता है कि हमारे अधिकांश रोग पेट से ही शुरू होते हैं। खासकर बच्चों व बुजुर्गों के लिये यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। जिससे बचने के लिये स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है।देश में बार-बार स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पिछले दिनों प्रदूषित पेयजल से होने वाली मौतों ने देश में खतरे की घंटी बजायी। घटना ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि इस दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में देश के सामने गंभीर स्वास्थ्य चुनौती पैदा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों तक पहुंचाए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की परख के लिये पानी के सैंपल लिए जाते हैं। साथ ही स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि बीते साल जल जीवन मिशन के तहत तमाम राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पेयजल सैंपलों की जांच की गई।

लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि कुल नमूनों के छब्बीस प्रतिशत को ही शुद्ध करने के प्रयास हुए हैं। आखिर देश के किसी भी भाग में पेयजल के सैंपल लेने का क्या औचित्य रह जाता है, जब प्रदूषित जल को लेकर उपचारात्मक प्रयास न किए जाएं। सवाल केवल ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का ही नहीं है, शहरी इलाकों में शुद्ध जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

लेकिन स्थानीय निकाय इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लेते। संपन्न लोग तो आरओ तथा फिल्टर आदि वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कमजोर वर्ग व सामान्य लोग दूषित पानी के उपयोग के लिये मजबूर होते हैं। स्वच्छ जल प्राप्त करना हर नागरिक का मौलिक व जीवन रक्षा का अधिकार जैसा है, जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। इंदौर की घटना से सबक लेकर स्थानीय निकायों और प्रशासन को पेयजल व सीवर लाइन को सुरक्षित दूरी पर रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

दलगत राजनीति से मुक्त हो राष्ट्रपति पद

पुष्परंजन

जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंच जाता है तो उसकी अगड़ी या पिछड़ी, पुरुष या महिला आदिवासी या वनवासी वाली कोई पहचान नहीं बचती। इस सब का लाभ उठाने की किसी भी कोशिश को जनतांत्रिक मूल्य...जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंच जाता है तो उसकी अगड़ी या पिछड़ी, पुरुष या महिला आदिवासी या वनवासी वाली कोई पहचान नहीं बचती। इस सब का लाभ उठाने की किसी भी कोशिश को जनतांत्रिक मूल्य और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए।देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक ही नहीं होता, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति को कैसे संबोधित किया जाये से लेकर राष्ट्रपति के साथ कैसा व्यवहार किया जाये जैसी बातें एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती हैं, और अपेक्षा की जाती है कि कोई इसका उल्लंघन नहीं करेगा।

हमारे राष्ट्रपति का सम्मान किसी व्यक्ति या पद का सम्मान मात्र नहीं है, वस्तुतः यह देश का सम्मान है, उस संविधान का सम्मान है, जिसके आधार पर हमारी समूची जनतांत्रिक व्यवस्था चलती है। इस पद की मर्यादा को देखते हुए कुछ ऐसी ही अपेक्षा उस व्यक्ति से भी की जाती है, जिसे देश इस पद पर बिठाता है। दलगत राजनीति से कहीं ऊपर होता है इस पद पर बैठा व्यक्तिङ्कपूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे राष्ट्र को संरक्षण भी देता है।आमतौर पर यह माना जाता है कि हमारा राष्ट्रपति विवादों से परे होगा। पिछले सात दशक से भी अधिक समय का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस पद पर बैठे व्यक्तियों ने कुल मिलाकर पद की गरिमा की रक्षा ही की है। ऐसे में जब किसी राष्ट्रपति के संदर्भ में विवादास्पद स्थितियां बनती हैं तो खेद भी होता है और आशंका भी होती है कि देश का यह सर्वोच्च पद विवादों के चलते अपनी गरिमा न खो दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हाल की बंगाल-यात्रा को लेकर जिस तरह का वातावरण बन रहा है, वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता।हम इस घटना को लेकर कोई टिप्पणी करें उससे पहले इस बात को रेखांकित किया जाना जरूरी है कि एक आदिवासी महिला का इस पद पर पहुंचना हम सबके लिए गौरव की बात है। वे पहली महिला नहीं हैं जो इस पद के लिए चुनी गयी हैं, पर एक आदिवासी महिला यदि अपनी योग्यता-क्षमता से देश की राष्ट्रपति बनती है तो महिलाओं अथवा आदिवासियों के एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने का ही उदाहरण नहीं है, यह हमारे जनतंत्र की परिपक्वता का भी एक गौरवशाली क्षण है। देश को इस पर गर्व होना चाहिए। हमें है इस बात का गर्व। इसलिए राष्ट्रपति, पद के अपमान को लेकर देश इतना संवेदनशील भी है। इस पद की गरिमा को कम करने की कोई भी घटना अथवा कोई भी कोशिश देश के जागरूक नागरिक को स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।अब बंगाल वाली घटना की बात। संथाल आदिवासियों की एक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति बंगाल गयी थीं। राष्ट्रपति जब भी किसी राज्य में जाते हैं, भले ही वह यात्रा सामाजिक हो अथवा सरकारी, तो उनके स्वागत का एक निश्चित तरीका होता है, जिसका पालन राज्य सरकार को करना होता है। इस प्रोटोकॉल में मुख्य रूप से यह बात शामिल है कि राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री अथवा कोई वरिष्ठ मंत्री स्वागत करने पहुंचता है।

यह संभव है कभी किन्हीं कारणों से इस व्यवस्था का पूरा पालन न हो पाता हो, पर ऐसा होने का कोई उचित कारण होना-दिखना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वागत के लिए नहीं पहुंची थीं। उन्होंने 'पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रम' और राष्ट्रपति की यात्रा की पूर्व सूचना न मिलने का हवाला देकर अपनी अनुपस्थिति का औचित्य ठहराया है। उनकी बात सही भी हो सकती है, पर ऐसे में वे अपने मंत्रिमंडल के किसी वरिष्ठ सहयोगी को वहां भेज कर अपना कर्तव्य निभा सकती थीं। मुख्यमंत्री की यह चूक हल्के से नहीं ली जानी चाहिए। वे चाहतीं तो चूक को स्वीकार करके विवाद की तल्खी कम कर सकती थीं। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा।

उत्तराखंड की राजधानी का अनसुलझा विवाद

सत्ताधीशों की उदासीनता

निरंजन शुक्ला

राजधानी केवल ईंट-पत्थर की इमारतों या विधानसभा की सीढ़ियों का नाम नहीं होती; यह राज्य के 'विज़न' और उसकी 'आत्मा' का प्रतिबिंब होती है। 25 साल बाद भी उत्तराखंड की सरकारें 'ग्रीष्मकालीन' और 'शीतकालीन' के जुमलोंमें उलझी हैं।चमोली ज़िले में स्थित भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में जब भी दो-तीन दिनों के लिए उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित होता है तो सीमांत हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड की स्थाई राजधानी का मुद्दा फिर गर्मा जाता है। नवम्बर, 2000 से लेकर अब तक राज्य गठन के 25 साल हो चुके हैं, लेकिन राज्य की राजधानी का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा है।

भाजपा की सरकार ने राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल तो दूर, यह घोषणा राज्य की राजधानी की मांग को लेकर एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाने वाले लोगों के गले भी नहीं उतरी। किसी एक स्थान पर महज कुछ दिनों के लिए विधानसभा सत्र आयोजित करने से वह स्थान राजधानी नहीं बन जाता! अगर लोग भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी मान भी लें, तो शीतकालीन या स्थाई राजधानी का सवाल अभी भी अनुत्तरित है। जिस भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, वहां पिछले छह वर्षों में केवल एक बार ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ, और वह भी बहुत संक्षिप्त।उत्तराखंड अकेला राज्य है, जिसकी राजधानी आज तक तय नहीं हो पाई। इसके लिए उत्तराखंड का अपना राजनीतिक तंत्र जिम्मेदार रहा है, जो राज्य गठन से लेकर अब तक राजधानी को लेकर एक राय नहीं बना सका। जब संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास हो गया था, तो उसी समय से राजधानी की तलाश शुरू हो गई थी। उस

समय जब विधायकों और सांसदों के बीच राजधानी को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रस्साकशी होने लगी, तो तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने यह मुद्दा उत्तराखंड के लोगों पर छोड़ दिया और तात्कालिक ढांचागत सुविधाओं को देखते हुए देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित किया। साथ ही कुमाऊं के लोगों को संतुष्ट करने के लिए नैनीताल को हाईकोर्ट दे दिया। आज ये दोनों शहर अपनी सीमित धारण क्षमता के कारण राजधानी और हाईकोर्ट के बोझ तले दबे हुए हैं। दोनों ही भूगर्भीय दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। नैनीताल की विकट स्थिति को देखते हुए स्वयं हाईकोर्ट को अपने लिए कोई नई जगह तलाशने के आदेश देने पड़े।केंद्र सरकार ने राजधानी के चयन की जिम्मेदारी उत्तराखंड (उत्तरांचल) सरकार पर छोड़ दी थी, इसलिए पहली नित्यानंद स्वामी सरकार ने इसके लिए दीक्षित आयोग का गठन कर दिया, जिसे छह माह के अंदर अपनी सिफारिशें देनी थीं। लेकिन आयोग उत्तराखंड की राजनीति से अपरिचित नहीं था, इसलिए उसने मामला आठ साल तक लटकाए रखा। फिर भी दीक्षित आयोग कायम रहा। 11 जनवरी, 2001 को गठित इस आयोग ने भारी जन दबाव के बाद 17 अगस्त, 2008 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जो दिसंबर, 2008 में विधानसभा में रखी गई। दीक्षित आयोग की यह रिपोर्ट भी उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति की पोल खोलने के लिए काफी है। आयोग के समक्ष 70 विधायकों में से केवल एक और पांच सांसदों में से भी एक ने अपनी राय दी।सर्वेक्षणों में जनता का बहुमत गैरसैंण के पक्ष में था, लेकिन आयोग के सामने लिखित राय देने वाले केवल 4-5 लोग ही इसके पक्ष में खड़े दिखे। आयोग में राय देने वाले अधिकांश लोगों ने अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दी। गढ़वाल के लोगों ने ऋषिकेश या देहरादून और कुमाऊं के लोगों ने रामनगर या काशीपुर को वरीयता दी। ऐसी स्थिति में आयोग ने देहरादून के रायपुर क्षेत्र को ही अपनी वरीयता दे दी।भराड़ीसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान 4 मार्च, 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हो गई। इस घोषणा की पुष्टि के लिए 8 जून, 2020 को आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई। भराड़ीसैंण के 'ग्रीष्मकालीन राजधानी' बनने के बाद पिछले छह वर्षों में केवल जून, 2022 में ही वहां वास्तविक ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ। एक-दो सत्र शीतकाल में भी हुए, लेकिन वे आधे-अधूरे ही थे! एक सप्ताह तक विधानसभा चलाना राजधानी चलाना नहीं होता।

रमजान का आखिरी जुमा: कल अदा होगी नमाज, दो बार अलविदा की भी संभावना

कल 13 मार्च को आखिरी जुमा होने के आसार, चांद 30 का हुआ तो 20 मार्च को भी नमाज

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। पवित्र माह रमजान में आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर मस्जिदों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस शुक्रवार कल यानी 13 मार्च को रमजान का आखिरी जुमा होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर नमाजियों में खास उत्साह देखा जा रहा है।

- **एसीपी बोले, सड़क पर नहीं अदा होगी नमाज, सर्किल के सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश**

उलेमाओं के अनुसार इस वर्ष रमजान के चांद की स्थिति के कारण दो बार अलविदा जुमा होने की भी संभावना बन रही है। यदि रमजान 29 दिनों का रहता है तो कल 13 मार्च को ही आखिरी जुम्मे की नमाज मानी जाएगी।

वहीं अगर रमजान 30 दिनों का होता है तो अगले शुक्रवार यानी 20 मार्च को भी अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जा सकती है। कस्बे के कारी नजरुल इस्लाम और हाजी मुफ्ती यासिर अरफात ने बताया कि रमजान के आखिरी जुमे को अलविदा जुमा कहा जाता है। यह कोई अलग नमाज नहीं होती, बल्कि सामान्य जुमे की तरह ही अदा की जाती है, लेकिन माह-ए-रमजान का अंतिम शुक्रवार होने के कारण इसका विशेष महत्व होता है। उन्होंने बताया कि मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ को देखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को नमाज अदा करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। रमजान के अंतिम दिनों में इबादत और दुआओं का सिलसिला भी तेज हो जाता है, जिससे मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है।

हैदरी मस्जिद में आयोजित मजलिस में बयान करते मौलाना अजीम रिज़वी।

सड़क पर नहीं अदा होगी नमाजः एसीपी बिल्हौर

एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह ने बताया कि अलविदा जुमा को लेकर सर्किल के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मस्जिदों के आसपास पुलिस बल तैनात रहेगा और नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस अराजक तत्वों पर विशेष नजर रखे है। ताकि माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहे।

हैदरी मस्जिद में मौला अली की याद में मजलिस

बिल्हौर(कानपुर)। इलियासपुर मकनपुर स्थित हैदरी मस्जिद में मौला अली की याद में मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस में उलेमाओं ने खिताब किया, वहीं बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर गम का इजहार किया।

- **उलेमाओं ने बयान में हजरत अली की शख्सियत और इंसानियत के पैगाम पर डाली रोशनी**

मजलिस की शुरुआत शोएब गाजी की सोजखानी से हुई। इसके बाद फराज जाफरी ने मौला अली की शान में शायरी पेश की, जिसे सुनकर मौजूद लोगों ने दाद दी।मुख्य वक्ता के रूप में अंबेडकर नगर से आए मौलाना अजीम रिजवी ने हजरत अली के जीवन और उनके आदर्शों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हजरत अली ने हमेशा इंसाफ और इंसानियत का रास्ता दिखाया तथा अपना पूरा जीवन जरूरतमंदों और मजलूमों की मदद में गुजारा। मजलिस के दौरान अंजुमने जाफरिया की ओर से नोहाखानी की गई और अकीदतमंदों ने सीना जनी कर गम का इजहार किया। आखिर में विशेष दुआ की गई । इस मौके पर हशम अब्बास नक़वी,तौसीफ रिजवी,नूरुल अरफ़ात जैनुल हयात, शाकर हुसैन, आदिल जाफरी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

सीएनजी बसें बंद होने पर सपा का विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते सपाई

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं बेहतर करने और बंद पड़ी सीएनजी बसों को दोबारा चलाने की मांग को लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी संजीव दीक्षित को सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग उठाई।

- **30 दिन में कार्रवाई न हुई तो आंदोलन की चेतावनी, अरौल तक बस सेवा बढ़ाने की मांग**

प्रदर्शन का नेतृत्व बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम और विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिल्हौर क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र, नौकरीपेशा लोग और महिलाएं कानपुर आते-जाते हैं। पहले किफायती सीएनजी बसें उनके लिए मुख्य सहारा थीं, लेकिन बस सेवा बंद होने से लोगों को महंगे निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। रचना सिंह गौतम ने कहा कि परिवहन सुविधाएं कम होने से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार को जल्द बस सेवा बहाल करनी चाहिए, ताकि छात्रों और आम यात्रियों को राहत मिल सके।

वहीं विनय यादव ने प्रशासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें कानपुर-बिल्हौर मार्ग पर बंद सीएनजी बसों का संचालन दोबारा शुरू करना, बस सेवा को बढ़ाकर अरौल तक करना, अरौल बस स्टॉप पर दोबारा बसों का ठहराव सुनिश्चित करना और हाईवे बाईपास से गुजरने वाली रोडवेज बसों को कस्बे के अंदर से चलाना शामिल है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 30 दिन के भीतर मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान सपा नेता लोकेश अवस्थी,पंकज यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

..तो परमिट खत्म होने पर बंद की गईं सीएनजी बसें

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वास्तव में सीएनजी बसों का 15 वर्ष का परमिट था। इसके बाद बसें कबाड़ की श्रेणी में आ जाती हैं। जिसके कारण उन्हें बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सीएनजी बसों के केंद्र से ग्रांट मिलती थी। लेकिन देखरेख की जिम्मेदारी परिवहन निगम के अफसरों के पास ही रहती थी। उन्होंने बताया कि सीएनजी बसों के बंद होने से सवारियों को परेशानी हो रही है। यह बात अधिकारियों के संज्ञान में है। जिसका समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रंगदारी व मारपीट के आरोपों में घिरे चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

ग्रामीणों की शिकायत पर शुरु हुई जांच, डीसीपी के निर्देश पर लाइन हाजिर

स्वराज इंडिया फालोअप

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। ककवन थाना क्षेत्र की नदीहा चौकी इंचार्ज को रंगदारी मांगने, मारपीट और धमकी देने के आरोपों के मामले में लाइन हाजिर कर दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसीपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं पूरे मामले की गहनता से जांच भी शुरू कर दी गई है।

मालूम हो कि नदीहा खुर्द निवासी नरेंद्र और पंकज मिश्रा ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए थे। नरेंद्र का आरोप है कि 17 फरवरी को चौकी इंचार्ज ने एक सिपाही के साथ उन्हें चौकी बुलाया और एक मामले में समझौता कराने का दबाव बनाते हुए 20 हजार रुपये की मांग की। रुपये देने से मना करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए डंडे से पिटाई करने का आरोप लगाया गया। नरेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद उन्हें दोबारा चौकी बुलाया गया, जहां हाथ-पैर बांधकर दबाव में उनके पक्ष में वीडियो बनवाया गया और शिकायत वापस लेने को कहा गया।

चौकी इंचार्ज पर मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप

वहीं नदीहा खुर्द निवासी पंकज मिश्रा ने भी चौकी इंचार्ज पर अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगाया है। पंकज के अनुसार, छह फरवरी की शाम करीब छह बजे उन्हें चौकी बुलाकर गाली-गलौज की गई और नरेंद्र के साथ जबरन समझौता कराने का दबाव बनाया गया।

मना करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बर्रा में तालाबंद घरों को निशाना बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में तालाबंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का बर्रा थाना पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब आठ लाख रुपये के जेवरात, नगदी तथा घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन बरामद किया गया है।

पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार बर्रा-7 और बर्रा-4 क्षेत्र में बंद पड़े दो मकानों में हाल ही में चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। इस संबंध में पीड़ित प्रदीप प्रजापति और हर्षित चौहान की तहरीर पर बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

- **तीन शातिर गिरफ्तार, 8 लाख के जेवर-नगदी और वारदात में प्रयोग किया गया पिकअप वाहन बरामद**

घटना की जांच के दौरान पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर विक्रम उर्फ विक्की उर्फ विराट, राज कश्यप और अंकित को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए लगभग आठ लाख रुपये के जेवरात और नगदी बरामद की है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई पिकअप भी कब्जे में ले ली गई है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में अन्य धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी विक्रम उर्फ विक्की के खिलाफ पहले से भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ईरान-इजरायल तनाव का बड़ा असर

यूपी में रसोई गैस का संकट गहराया !

» लखनऊ और कानपुर समेत कई शहरों में लंबी कतारें, कालाबाजारी की शिकायतें तेज; गरीब और उज्वला लाभार्थी अधिक प्रभावित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिलेंडर का संकट गहरा गया है। फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई कमी अब गंभीर रूप लेती दिख रही है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज और गोरखपुर समेत अनेक शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में लगभग चार करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब पांच से छह लाख सिलेंडरों की खपत होती है, लेकिन आपूर्ति में कमी के कारण वितरण प्रभावित हो रहा है। गैस एजेंसियों के अनुसार आपूर्ति सामान्य से कम होने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ गया है।

गरीब और उज्वला लाभार्थी सबसे ज्यादा प्रभावित

गैस संकट का सबसे अधिक असर गरीब परिवारों और प्रधानमंत्री उज्वला योजना के लाभार्थियों पर पड़ रहा है। लखनऊ की झुग्गी बस्ती में रहने वाली राधा देवी बताती हैं कि उन्हें पिछले दस दिनों से सिलेंडर नहीं मिला है, जिससे परिवार को लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है।

धुएं के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है।

बस्ती जिले में कई महिलाएं सुबह चार बजे से गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। प्रदेश में उज्वला योजना के करीब डेढ़ करोड़ लाभार्थी हैं, जिनमें से कई पहले से ही आधार लिंकिंग और अन्य प्रक्रियाओं की दिक्कतों से जूझ रहे थे। मौजूदा संकट ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है।

रसोई गैस की कमी का असर छोटे व्यापारियों और खाद्य कारोबार पर भी पड़ रहा है। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में चाट का ठेला लगाने वाले रामू का कहना है कि गैस न मिलने से उनका काम लगभग ठप हो गया है। मजबूरी में वे कोयले की भट्ठी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। मुजफ्फरनगर के होटल संचालकों के अनुसार व्यावसायिक सिलेंडर की कमी से कई रसोईघर प्रभावित हुए हैं। टिफिन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं, जिससे छात्र और कामकाजी लोग भोजन के लिए परेशान हैं।

कालाबाजारी की भारी शिकायतें

कई जिलों में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बरेली में घरेलू सिलेंडर दो हजार पांच सौ से तीन हजार रुपये तक में बिकने की खबरें हैं। कानपुर और नोएडा में प्रशासन ने गोदामों पर छापेमारी कर जमाखोरी के मामलों का खुलासा किया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि संपन्न वर्ग के लोग अतिरिक्त कीमत देकर आसानी से सिलेंडर खरीद लेते हैं, जबकि गरीब उपभोक्ताओं को एजेंसियों पर लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है।

सरकार का दावा और कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालाबाजारी पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा कई जिलों में छापेमारी तेज कर दी गई है। तेल कंपनियां पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही हैं और उपभोक्ताओं से टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की जा रही है।हालांकि जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ की सरिता बताती हैं कि पांच दिनों से गैस न मिलने के कारण उनके बच्चों को कई बार बिना गर्म भोजन के सोना पड़ रहा है। गोरखपुर में एक विधवा महिला को पड़ोसियों से उधार लेकर खाना बनाना पड़ रहा है, जबकि प्रयागराज के एक स्ट्रीट वेंडर ने गैस न मिलने के कारण अपना काम अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात लंबे समय तक बने रहे तो आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। ऐसे में राज्य सरकार और तेल कंपनियों को वितरण व्यवस्था मजबूत कर गरीब उपभोक्ताओं तक गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, ताकि रसोई और छोटे कारोबारों पर पड़ रहा दबाव कम हो सके।

तीन दिन से कम की बीमारी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए और व्यावहारिक स्थितियों को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि बहुत कम समय (तीन दिन से कम) के मेडिकल अवकाश के लिए कर्मचारियों से मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एक दिन या बहुत कम समय की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाकर सर्टिफिकेट बनवाना व्यावहारिक नहीं है। छोटी बीमारी (जैसे सामान्य थकान या पेट दर्द) में हर व्यक्ति तुरंत डॉक्टर के पास नहीं भागता बल्कि घर पर ही आराम करना बेहतर समझता है। ऐसे में सर्टिफिकेट की मांग करना कर्मचारी पर मानसिक और आर्थिक बोझ डालना है। कंपनी का पक्ष था कि यदि मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई तो कर्मचारी छुट्टी की सुविधा का गलत इस्तेमाल करेंगे और अनुशासन बिगड़ेगा।

The Associated Cement Companies Ltd. vs Cement Workers Kamdar Union And Ors. on 17 March, 1972

Equivalent citations: AIR1972SC1552, [1973(26)FLR306], 1972LABLC822, (1972)IILLJ40SC, (1972)4SCC23, AIR 1972 SUPREME COURT 1552, 1972 4 SCC 23, 1972 LAB. I. C. 822, 1972 2 LABLJ 40, 24 FACLR 306, (1972) 2 LAB LJ 40, 41 FJR 395

Bench: C.A. Vaidialingam, D.G. Palekar, K.K. Mathew

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि छोटी अवधि की बीमारी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग करना न केवल अव्यावहारिक है बल्कि यह कर्मचारियों के लिए अनावश्यक परेशानी का कारण बनता है। इस निर्णय के बाद अब कार्यस्थलों पर निम्नलिखित बदलाव देखने को मिल सकते हैं- छोटी अवधि की बीमारी को अब भरोसे के आधार पर देखा जाएगा। कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी के लिए क्लीनिक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बीमारी की स्थिति में कर्मचारी बिना तनाव के आराम कर सकेंगे कि उन्हें फिटनेस या मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि नियम अनुशासन के लिए होने चाहिए न कि कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि कानून में मानवीय संवेदनाओं और सामान्य व्यवहार का स्थान सर्वोपरि है।

सेरुवा की 36 बीघे बंजर जमीन बनेगी हरित पट्टी

वन विभाग लगाएगा 15 हजार तक के पौधे

» तीन वर्ष की लीज पर ली गई भूमि पर शुरू हुई मेड़बंदी

» बरसात में आम, जामुन और बबूल के होंगे पौधारोपण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात (माती)। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में वन विभाग ने ब्लॉक सरवनखेड़ा के सेरुवा गांव में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। वर्षों से अनुपयोगी पड़ी करीब 36 बीघे सरकारी भूमि को अब हरित पट्टी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत आगामी वर्षा ऋतु में यहां करीब 15 हजार पौधों का वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।यह भूमि सरकारी अभिलेखों में अकबरपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम दर्ज है और लंबे समय से परती पड़ी थी। ग्राम पंचायत और विद्यालय प्रबंधन समिति की पहल पर इस भूमि के बेहतर उपयोग का प्रस्ताव वन विभाग को भेजा गया था। प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए विभाग ने भूमि को तीन वर्षों की लीज पर लेकर वृक्षारोपण योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार सेरुवाङ्कलोहारी मार्ग के दोनों ओर फैली करीब साढ़े सात हेक्टेयर भूमि पर इस परियोजना को विकसित किया जाएगा। वृक्षारोपण से पहले भूमि को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए चारों ओर मजबूत मेड़बंदी कराई जा रही है। पिछले तीन दिनों से जेसीबी मशीनों की मदद से बड़े स्तर पर मेड़बंदी और भूमि समतलीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है, ताकि लगाए जाने वाले पौधों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। ग्राम प्रधान मंगल सिंह परिहार ने बताया कि भूमि वर्षों से अनुपयोगी पड़ी थी और उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। ग्राम पंचायत और विद्यालय प्रबंधन समिति ने सामूहिक रूप से निर्णय लेकर वन विभाग से संपर्क किया, जिसके बाद विभाग ने यहां वृक्षारोपण योजना को स्वीकृति दी।वन रक्षक सची तोमर ने बताया कि लगभग साढ़े सात हेक्टेयर क्षेत्रफल में 15 हजार गड्ढों की खुदाई कराई जाएगी।

आगामी वर्षा ऋतु में इन गड्ढों में आम, जामुन और बबूल जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और दीर्घजीवी पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना से क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ेगा और पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित पड़ी इस जमीन पर वृक्षारोपण होने से क्षेत्र का पर्यावरण सुधरेगा। आने वाले समय में यह स्थान हरित पट्टी और जैव विविधता के छोटे केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ और हराभरा वातावरण मिलेगा।

वन विभाग ने 36 बीघा जमीन की मेड़बंदी शुरू की

एक नजर में....

- सेरुवा गांव में 36 बीघे परती भूमि को हरित पट्टी में बदला जाएगा।
- वन विभाग ने भूमि को तीन वर्ष की लीज पर लिया है।
- करीब 15 हजार पौधों का रोपण आगामी वर्षा ऋतु में किया जाएगा।
- जेसीबी से मेड़बंदी और भूमि संरक्षण का कार्य तेज़ी से जारी।
- आम, जामुन और बबूल जैसे दीर्घजीवी पौधे लगाए जाएंगे।
- परियोजना से क्षेत्र में हरित आवरण और जैव विविधता बढ़ने की उम्मीद।

स्कूली बस की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत

घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र की, परिजन बदहवास

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। गढ़िया गांव के पास एक निजी स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, गढ़िया गांव निवासी 45 वर्षीय राघवेंद्र पुत्र मंगल सिंह अपनी बाइक से खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बच्चों को छोड़कर लौट रही एक निजी स्कूल बस ने उनकी बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राघवेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। परिजनों को जानकारी दी गई, जिसके बाद राघवेंद्र के भांजे शिवम उन्हें जीवित समझकर बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. अमित ने जांच के बाद राघवेंद्र को मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भांजे शिवम ने बताया कि राघवेंद्र पेशे से किसान थे और अपने परिवार के मुख्य सहारा थे। उनके तीन बेटे और दो बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है। राघवेंद्र की मौत की खबर से परिवार में शोक का माहौल है।घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मंगलपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।मृतक के परिवार में उनकी पत्नी साधना देवी और बच्चे आंशिका, विशाल, शिवा तथा शिवम हैं।

टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल हवासपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सा अधिकारी ने घटना की सूचना मंगलपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बस को हिरासत में ले लिया।

जिला बार एसोसिएशन चुनाव

पहले दिन अधिवक्ताओं ने दाखिल किए नामांकन

अध्यक्ष पद के लिए जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान और बलराम सिंह मैदान में, 25 मार्च को होगा मतदान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिला न्यायालय परिसर में बुधवार को जिला बार एसोसिएशन, कानपुर देहात के वार्षिक चुनाव-2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए अपने-अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के दौरान न्यायालय परिसर में भारी सुरक्षाबल की मौजूदगी रही और अधिवक्ताओं के बीच चुनाव को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला।अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान और बलराम सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए प्रभा यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र, मंत्री पद के लिए क्षमता सिंह ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया।संयुक्त मंत्री (प्रशासन) पद के लिए जय गोपाल, संयुक्त मंत्री (प्रकाशन) पद के लिए अवधेश कुमार तथा संयुक्त मंत्री (पुस्तकालय) पद के लिए शशिबिंदु ने अपने-अपने नामांकन दाखिल किए।वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए गोपी सिंह, रईस अहमद, राहुल कुमार और चन्द्रलता ने नामांकन किया, जबकि कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए श्याम कुमार, अजीत सिंह, अनुज प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार और श्याम सुन्दर ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 12 मार्च 2026 को भी प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 13 मार्च 2026 को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) तथा नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 मार्च 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।नामांकन के दौरान चुनाव समिति के चेयरमैन सम्पत लाल तथा सदस्य रमेश चन्द्र सिंह गौड़, जयगोविंद सिंह, रहीश अहमद कुरैशी, रविशंकर वर्मा और हिमांशु गुप्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव एवं महामंत्री घनश्याम सिंह राठौर भी उपस्थित रहे।

सेंगुर नदी में डूबे दो युवकों में एक का शव 20 घंटे बाद मिला दूसरे की तलाश जारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मावर गांव के पास स्थित सेंगुर नदी में नहाने गए दो युवक गहरे पानी में डूब गए। घटना के करीब 20 घंटे बाद एसडीआरएफ टीम ने एक युवक का शव बरामद कर लिया, जबकि दूसरे युवक की तलाश देर शाम तक जारी रही। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

कानपुर नगर निवासी 25 वर्षीय रवि गुप्ता पुत्र विनोद कुमार और 27 वर्षीय अभिषेक शर्मा पुत्र शिव कुमार अपने एक दोस्त के साथ मंगलवार को मावर गांव के पास सेंगुर नदी किनारे घूमने और पिकनिक मनाने आए थे। तीनों दोस्तों ने नदी किनारे बैठकर कुछ देर समय बिताया और इसके बाद नहाने के लिए नदी में उतर गए। बताया जाता है कि नहाते समय रवि गुप्ता और अभिषेक शर्मा अचानक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते दोनों डूब गए। सुबह एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

काफी देर तक चले अभियान के बाद लगभग 20 घंटे बाद अभिषेक शर्मा का शव घटनास्थल के पास बने गहरे कुंड से बरामद कर लिया गया। शव बाहर निकलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उधर दूसरे युवक रवि गुप्ता की तलाश के लिए एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों ने दिनभर नदी में सर्च ऑपरेशन आज भी अभियान जारी है लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका।

भोगनीपुर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दूसरे युवक की तलाश के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

डंपर की टक्कर से सब्जी लदा लोडर पलटा, तीन व्यापारी घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद, कानपुर देहात। क्षेत्र में सुबह एक सड़क हादसे में सब्जी लेकर आ रहा लोडर डंपर की टक्कर से पलट गया। हादसे में लोडर सवार तीन लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य कर घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा।रसूलाबाद क्षेत्र के असालतगंज निवासी जनक और राहुल तथा एकघरा निवासी घनश्याम सुबह करीब साढ़े आठ बजे तीनों लोग लोडर में सब्जी लेकर बिल्हौर से रसूलाबाद की ओर आ रहे थे। तभी सरैया और हरलाल निवादा गांव के बीच पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने लोडर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह लोडर में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा। सूचना मिलने पर आरक्षी सूर्यसेन यादव और नीरज कुमार मौके पर पहुंचे। चौकी प्रभारी तिश्ती बृजेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना करने वाले डंपर को पकड़ लिया गया है।

महिला व परिजनों से मारपीट, कार में तोड़फोड़, तीन के खिलाफ केस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद, कानपुर देहात। कोतवाली क्षेत्र के कुर्सी खेड़ा गांव में महिला व उसके परिजनों के साथ मारपीट करने और कार को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कुर्सी खेड़ा गांव निवासी सुनीता देवी पत्नी अमित कुमार सिंह ने कोतवाली रसूलाबाद में दी गई तहरीर में बताया कि 3 मार्च को शाम लगभग 5-30 बजे गांव के ही हिमांशु सिंह पुत्र लवकुश सिंह, रोहित सिंह पुत्र लवकुश सिंह व लवकुश सिंह ने अचानक गाली-गलौज शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार जब उन्होंने और उनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि हमलावरों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर न्याय की मांग की है। कोतवाल एसएन सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्नत खेती की सीख लेने उमर्दा पहुंचे कानपुर देहात के किसान

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 50 कृषकों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया अध्ययन भ्रमण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात, माती।एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक उद्यानिकी तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से गुरुवार को उद्यान विभाग की ओर से शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत जनपद के करीब 50 प्रगतिशील किसानों के दल को कन्नौज जनपद के उमर्दा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का अध्ययन भ्रमण कराया गया।

उद्यान निरीक्षक घनश्याम के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने केंद्र में स्थापित आधुनिक सब्जी उत्पादन प्रणाली, पौधशाला और संरक्षित खेती की उन्नत तकनीकों का अवलोकन किया।

इस दौरान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दलगंजन यादव और आशीष कुमार ने किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से सब्जी उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने किसानों को साग-भाजी की उन्नत खेती, नर्सरी प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण सब्जी पौध उत्पादन, उन्नत किस्मों के चयन तथा सीमित संसाधनों में अधिक

उत्पादन प्राप्त करने की आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। साथ ही बाजार में बेहतर गुणवत्ता की उपज मिलने से किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है और उनकी आय में भी वृद्धि होती है।

इस अवसर पर विशेषज्ञों ने संरक्षित खेती (पॉलीहाउस व नेट हाउस), संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जैविक खाद के उपयोग तथा रोग एवं कीट नियंत्रण की नवीन तकनीकों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। किसानों ने केंद्र में स्थापित विभिन्न प्रायोगिक इकाइयों का अवलोकन कर आधुनिक कृषि पद्धतियों को नजदीक से समझा और विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया।

उद्यान निरीक्षक घनश्याम ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को आधुनिक कृषि एवं उद्यानिकी तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऐसे शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण से प्राप्त ज्ञान को किसान अपने खेतों में अपनाकर उत्पादन बढ़ाने के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। भ्रमण में शामिल किसानों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए बेहद लाभकारी हैं, क्योंकि इससे उन्हें आधुनिक खेती की नई तकनीकों को सीखने और उन्हें व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है।

जमवाय माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकासखंड मलासा के मलासा गांव स्थित प्रसिद्ध जमवाय माता मंदिर में बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के दूर-दराज गांवों से हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और माता के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही

मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी, जो देर शाम तक जारी रही। पूरे क्षेत्र में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत विधि-विधान से माता के पूजन-अर्चन और आरती के साथ हुई। इसके बाद आयोजित विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं को पूड़ी, सब्जी, हलवा समेत अन्य प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर माता से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।

भंडारे के आयोजन को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन के बीच श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते नजर आए,

जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने बताया कि जमवाय माता मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यशवंत सिंह, प्रमोद, विपिन, माधव, झल्लर, चंद्रमोहन, दीपू सिंह, अरविंद सिंह और विकास सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

एलपीजी गैस सिलिंडर की मार, मचा चहुंओर हाहाकार

एलपीजी संकट की चपेट में रेलवे का किचन ट्रेनों में भोजन सेवा पर मंडराया खतरा

» आगरा कैंट बेस किचन में सिर्फ दो दिन का गैस स्टॉक

» आईआरसीटीसी वेंडरों में चिंता; अस्पताल, होटल और छात्र मेस भी प्रभावित

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

आगरा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उससे प्रभावित गैस आपूर्ति का असर अब रेल यात्रियों की थाली तक पहुंच गया है। आगरा में एलपीजी की किल्लत के कारण रेलवे के बेस किचन पर संकट गहरा गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन स्थित बेस किचन में गैस सिलेंडरों का स्टॉक केवल दो दिन का बचा है। ऐसे में यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो यहां से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है। आईआरसीटीसी के अधिकृत वेंडरों के अनुसार आगरा कैंट बेस किचन से रोजाना हजारों यात्रियों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। खासतौर पर बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रतिदिन करीब 600

यात्रियों और मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में 700 से अधिक यात्रियों के लिए यहीं से भोजन बनाकर भेजा जाता है। लेकिन वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति घटने के कारण किचन में गैस का संकट खड़ा हो गया है। वेंडरों का कहना है कि यदि सिलेंडर समय पर नहीं मिले तो ट्रेनों में यात्रियों को भोजन सेवा रोकनी पड़ सकती है।

गैस संकट का असर केवल रेलवे तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलिवरी सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेनों में भोजन सप्लाई करने वाले एक एजेंट ने गैस की कमी के कारण पिछले दो दिनों से डिलिवरी सेवा बंद कर दी है। शहर में करीब एक दर्जन एजेंट यात्रियों को ट्रेन में उनकी पसंद का भोजन उपलब्ध कराते हैं। यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो यह सुविधा भी पूरी तरह ठप हो सकती है।स्टेशन के आसपास स्थित ढाबों और छोटे होटलों की स्थिति भी चिंताजनक है। कई संचालक मजबूरी में सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे हैं, जिससे भोजन के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पूड़ी-सब्जी और अन्य नाश्ता बेचने वाले वेंडरों का कहना है कि यदि जल्द गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो किचन बंद करने की नौबत आ सकती है। एलपीजी संकट का असर उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी महसूस किया जा रहा है। लखनऊ के बड़े अस्पतालों और छात्रावासों में गैस की कमी के कारण भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में बुधवार को रसोई में सिलेंडर की कमी के चलते मरीजों को पर्याप्त रोटियां तक नहीं मिल सकीं। वहीं मेडिकल छात्रों की मेस में भी कई जगह भोजन नहीं बन पाया, जिससे छात्रों को बाहर होटलों का रुख करना पड़ा।

पर्यटन नगरी आगरा के होटल और रेस्टोरेंट भी इस संकट से जूझ रहे हैं। कई प्रतिष्ठानों ने सीमित मेन्यू पर काम शुरू कर दिया है, जबकि कुछ ने नई बुकिंग तक रोक दी है। होटल कारोबारियों का कहना है कि यदि एलपीजी की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो पर्यटन और होटल उद्योग को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव का असर अब स्थानीय स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है।

गैस पेट्रोल एवं डीजल पर्याप्त उपलब्ध, बुकिंग होने पर ही गैस उपभोक्ता तक पहुंचाएं

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रूखाबाद द्य जनपद की सभी गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पम्प संचालकों के साथ आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम विक्रय प्रबंधक एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में गैस, पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है तथा कहीं भी किसी स्तर पर इनकी आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है।

» डीएम ने बैठक कर दिए कई निर्देश, बैठक में अनुपस्थित संचालकों को कारण बताओं नोटिस जारी

» नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें

जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे अपनी एजेंसियां प्रातः निर्धारित समय पर खोलना सुनिश्चित करें तथा बुकिंग के एक से दो दिन के भीतर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस की डिलीवरी उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस उपभोक्ता द्वारा बुकिंग की गई है, उसी को गैस सिलेंडर की डिलीवरी दी जाए।

सीएससी0 केंद्रों पर गैस केवल उसी स्थिति में दी जाए जब संबंधित उपभोक्ता की बुकिंग हो तथा किसी भी दशा में वहां 100 किलोग्राम से अधिक स्टॉक न रखा जाए। साथ ही स्टॉक की स्थिति एवं केवाईसी प्रक्रिया का प्रदर्शन गैस एजेंसी के शोरूम के साथ-साथ गोदाम पर भी किया जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प स्वामी अपने स्टॉक की स्थिति को देखते हुए अग्रिम रूप से धनराशि जमा कराकर गैस, डीजल एवं पेट्रोल की आपूर्ति समय से मंगाना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी दशा में बोतल, केन अथवा खुले पात्र में पेट्रोल की बिक्री न की जाए तथा पेट्रोल की बिक्री केवल वाहनों की टंकियों में ही की जाए।

इस संबंध में सूचना सभी पेट्रोल पम्पों पर प्रदर्शित की जाए। डीजल की बिक्री के संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को कृषि कार्य हेतु अनुमन्य मात्रा से अधिक डीजल एक बार में न दिया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में गैस सिलेंडर, डीजल अथवा पेट्रोल खरीदकर जमाखोरी करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए। सभी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा के अनुसार ही ईंधन की आपूर्ति की जाए।

यदि कहीं अधिक मूल्य वसूलने अथवा घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया कि पुलिस द्वारा जनपद के सभी गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पम्पों का समय-समय पर रैंडम निरीक्षण किया जाएगा।

साथ ही भ्रामक सूचना फैलाने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए

नो हेलमेट, नो फ्यूल÷ अभियान का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक में अनुपस्थित पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी संचालकों को कारण बताओ नोटिस/स्पष्टीकरण जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

अयोध्या

सिलेन्डर की मारामारी, बंद हुई राम रसोई

वैश्विक जंग का असर रामनगरी तक गैस संकट से बंद हुई 'राम रसोई'

एलपीजी की किल्लत से अयोध्या में पहली बार ठंडे पड़े सेवा के चूल्हे, सरकार कह रही सब अफवाह

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्याधाम। दुनिया के किसी दूर देश में छिड़ी जंग की आंच अब रामनगरी अयोध्या तक पहुंच गई है। एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत के चलते राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन कराने वाली प्रसिद्ध राम रसोई के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। पिछले आठ वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है

जब सेवा और भक्ति का यह केंद्र गैस की कमी के कारण बंद करना पड़ा।रसोई प्रबंधन का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई अचानक ठप हो गई, जिससे भोजन बनाना असंभव हो गया। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स इसी संकट से जूझ रहे हैं। दिलचस्प यह है कि जमीन पर गैस एजेंसियों के बाहर सुबह तीन बजे से कतारें लग रही हैं, जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है– अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर रामनगरी में सेवा के चूल्हे आखिर क्यों बुझ गए?

रंग, रस और राग में डूबा बार एसोसिएशन का होली मिलन

जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने अधिवक्ताओं संग गाए होली गीत, कवियों ने बिखेरा हास्य और रंग

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या की ओर से बुधवार को आचार्य नरेंद्र देव सभागार में होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा रहे। उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ होली गीत गाकर कार्यक्रम में रंग भर दिए और अपने संबोधन में कहा कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों के मिलन का पर्व है। इस दौरान उन्होंने 卐गले मिल रहे रंग卐 शीर्षक से काव्य पाठ भी किया।कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह ने हास्य चुटकुलों से माहौल को हल्का-फुल्का बनाया, वहीं राजीव पांडेय और राम शंकर यादव ने काव्य पाठ प्रस्तुत किया। कवि तारा चंद तनहा, एसीजेएम महेंद्र सिंह पासवान, अधिवक्ता सोम नाथ तिवारी और वरिष्ठ कवि अशोक टाटांबरी ने भी अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया।

सिविल जज स्वर्ण माला सिंह और प्रत्यूष आनन्द मिश्रा ने भी प्रस्तुति दी।

अंत में सीजेएम सुधांशु शेखर उपाध्याय ने काशी की होली पर गीत गाकर समां बांध दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने की और संचालन हेमंत त्रिपाठी ने किया।

राष्ट्रपति के स्वागत में अयोध्या का 'सुरक्षा महायज्ञ'

» रामनगरी में वीआईपी प्रोटोकॉल की कसौटी पर प्रशासन, श्रद्धालुओं की सुविधा का भी दिया भरोसा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी एक बार फिर वीआईपी आगमन की तैयारियों के केंद्र में है। माननीय राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर श्रीराम जन्मभूमि परिसर के पीएफसी सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चम्पत राय, एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार, मंडलायुक्त राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन बर्मा और जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे सहित प्रशासनिक व पुलिस अफसरों की पूरी फौज मौजूद रही।बैठक में सुरक्षा से लेकर यातायात, पार्किंग, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग और वीआईपी मूवमेंट तक हर बिंदु पर गहन मंथन हुआ।

अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि राष्ट्रपति के आगमन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

हालांकि प्रशासन का दावा है कि कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

अब सवाल यही है–क्या वीआईपी प्रोटोकॉल और आम श्रद्धालुओं की आस्था के बीच संतुलन वास्तव में कायम रह पाएगा, या फिर रामनगरी एक बार फिर 'सुरक्षा घेरों' में कैद नजर आएगी?

अयोध्या की भव्यता विश्व को दे रही नई सांस्कृतिक दिशा

रामनगरी में वीएचपी नेता का भव्य स्वागत, रामलला के दर्शन कर अभिभूत हुए

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्याधाम। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद से जुड़े यशवंत जी अयोध्याधाम पहुंचे और प्रभु श्री रामलला के दिव्य दर्शन कर पूजन-अर्चन किया। उनके साथ पहुंचे परिजनों का अयोध्या में संत परंपरा के प्रतिष्ठित महंत संत दास जी महाराज ने अंगवस्त्र और रामचरितमानस,विनय पत्रिका, दुर्गासप्तशती, भगवदगीता आदि ग्रंथो को भेंट कर भव्य स्वागत किया।

महंत संत दास जी ने अयोध्याधाम के आध्यात्मिक वैभव और तेजी से हो रहे विकास को राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम की नगरी अब आस्था, संस्कृति और विकास का वैश्विक केंद्र बन रही है। स्वागत से अभिभूत यशवंत जी ने कहा कि श्रीराम मंदिर की भव्यता और अयोध्या का परिवर्तन मन को गहराई से स्पर्श करता है। उन्होंने कहा कि यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि भारत की सनातन आस्था और सांस्कृतिक गौरव का पुनर्जागरण है।

पश्चिम एशिया जंग का नया मोर्चा!

कैलिफोर्निया पर ड्रोन हमले की आशंका

❍ एफबीआई ने जारी किया हाई अलर्ट, ईरान ने रखीं युद्ध समाप्ति की तीन शर्तें

❍ होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ा तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराया खतरा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते टकराव ने अब वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने कैलिफोर्निया में संभावित ड्रोन हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि यदि युद्ध और बढ़ता है तो ईरान किसी अज्ञात जहाज से ड्रोन (यूएवी) लॉन्च कर अमेरिकी पश्चिमी तट पर हमला करने की रणनीति अपना सकता है। इस खतरे को देखते हुए कैलिफोर्निया पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस बीच पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा लगातार फैल रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल के अलावा सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है।

एक नजर में...

- एफबीआई ने कैलिफोर्निया में संभावित ड्रोन हमले की चेतावनी दी
- ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हितों से जुड़े संस्थानों को निशाना बनाने की धमकी दी
- होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर फायरिंग से वैश्विक व्यापार पर असर
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल तेल भंडार जारी करने की घोषणा की
- कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां खाड़ी देशों से कर्मचारियों को निकाल रही हैं
- दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने और बंदरगाह पर ईंधन टैंक में आग की घटनाएं

ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान "धमकियों से डरने वाला देश नहीं है" और यदि दबाव बढ़ाया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी ओर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने युद्ध समाप्त करने के लिए तीन प्रमुख शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के अधिकारों को मान्यता देनी होगी, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी और भविष्य में ईरान पर हमला न करने की अंतरराष्ट्रीय गारंटी देनी होगी।

इसी बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी के बावजूद प्रवेश करने वाले दो वाणिज्यिक जहाजों पर गोलीबारी की। ओमान की नौसेना ने 20 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया, जबकि तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य लंबे समय तक प्रभावित रहा तो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और एलएनजी की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सदस्य देशों को अपने रणनीतिक भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है, ताकि वैश्विक बाजार में कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। उधर संयुक्त राष्ट्र और जी-7 देशों ने क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि संघर्ष फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने दुबई समेत खाड़ी देशों से अपने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है।

आगे युद्ध में क्या हो सकता है

- अमेरिका और इजरायल ईरान के सैन्य ठिकानों पर और बड़े हमले कर सकते हैं
- ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को आंशिक रूप से बंद कर सकता है
- ड्रोन और मिसाइल हमलों का दायरा खाड़ी देशों से बाहर भी फैल सकता है
- वैश्विक साइबर हमलों और आर्थिक प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो सकता है
- संयुक्त राष्ट्र या जी-7 के दबाव से युद्धविराम की कोशिश तेज हो सकती है

क्या तेल और गैस की कमी बढ़ेगी?

- दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी की आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य से होती है
- यदि मार्ग बाधित हुआ तो वैश्विक बाजार में तेल कीमतों में तेज उछाल संभव
- एशिया और यूरोप के कई देशों को गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है
- शिपिंग बीमा और परिवहन लागत बढ़ने से ऊर्जा महंगी होगी
- भारत समेत तेल आयात करने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।

छुट्टी से निवेश तक सब दर्ज करना होगा पोर्टल पर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। अब सभी विभागों को अपने कर्मचारियों के अवकाश से संबंधित पूरा विवरण 25 मार्च तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश में कहा गया है कि राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है तथा अवकाश की स्वीकृति भी इसी पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जानी है। हालांकि समीक्षा में पाया गया कि कई विभागों में अवकाश से जुड़ी जानकारी अधूरी या आंशिक रूप से ही दर्ज की गई है। इसलिए सरकार ने सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को तय समय सीमा में पूरा डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।इसी के साथ सरकार ने कर्मचारियों की संपत्तियों और निवेश की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-21 और नियम-24 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक की राशि शेयर, स्टॉक या अन्य किसी निवेश में लगाता है तो उसे इसकी जानकारी विभागाध्यक्ष को देनी होगी और धन के स्रोत का विवरण भी देना पड़ेगा।साथ ही चल संपत्ति के मामले में भी नियम कड़े किए गए हैं। अब दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल संपत्ति की खरीद पर सूचना देना अनिवार्य होगा।

13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की परमीशन

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया (इच्छा मृत्यु) की अनुमति दे दी है।करीब 13 वर्षों से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हरीश राणा के मामले में अदालत ने परिवार की गुहार और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह संवेदनशील फैसला सुनाया।

अदालत के निर्देश के अनुसार हरीश राणा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया मानवीय संवेदनाओं और गरिमा के साथ पूरी हो सके। करीब 13 साल से हरीश राणा अचेत अवस्था में जीवन रक्षक चिकित्सा पर निर्भर हैं। लंबे समय से चल रही इस स्थिति के कारण परिवार मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। इसी वजह से परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

➪ गाजियाबाद निवासी मरीज को पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी

➪ परिवार की गुहार और मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पूरी तरह चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में और स्थापित कानूनी मानकों के अनुरूप ही अपनाई जाएगी, ताकि मरीज की गरिमा और मानवीय संवेदनाओं का पूरा ध्यान रखा जा सके।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com